उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना का विकास *1967 – 1977* – हरित क्रांति के विशेष सन्दर्भ में

डॉ0 सुशील पाण्डेय

उत्तर प्रदेश में 1966–1967 से हरित क्रांति प्रारम्भ हुई जिसने उत्तर प्रदेश में कृषि का चरित्र बदल दिया। कृषि के आधुनिकीकरण और तकनीकी के इस्तेमाल से कृषि उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हुई इसका लाभ मुख्यतः कृषि से जुड़ी हुई उन पिछड़ी जातियों को हुआ जो अभी तक राजनीति में प्रभावशाली नहीं थीं। आजादी के बाद में देश में लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू हुई और जमींदारी उन्मूलन से बड़े पैमाने पर भूमि पिछड़ी जातियों को प्राप्त हुई। इस शोध पत्र का उद्देश्य यह प्रमाणित करना है कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों और हरित क्रांति से पिछड़ी जातियों को राजनीतिक पहचान प्राप्त हुई और राजनीतिक चेतना से उनकी स्थिति मजबूत हुई। 1960 के दशक में भारत सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में नये पैकेज की घोषणा की गई जिसमें उन्नति बीज और उन्नति कृषि उपकरणों का उपयोग किया गया इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। हरित क्रांति ने उत्तर भारत में मुख्यतः गेहूँ के उत्पादन को प्रभावित किया अर्थात् इस प्रभाव ने दोआब के जिलों और राज्य के पश्चिमी भाग को ज्यादा फायदा पहुंचाया। पिछड़े वर्ग के किसानों में राजनीतिक चेतना और नेतृत्व उन्हीं क्षेत्रों में उभरकर सामने आया जो मुख्यतः हरित क्रांति से प्रभावित थे।

जमींदारी उन्मूलन के बाद भी राजपूत ब्राह्मण भूमिहार, कायस्थ जैसी जातियों का राजनीतिक वर्चस्व बना रहा क्योंकि इनके पास आर्थिक शक्ति और नेतृत्व की क्षमता थी। इन जातियों का स्थानीय संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों पर नियन्त्रण था। 1966 तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यतः उच्च जातियों का ही वर्चस्व बना रहा जमींदारी उन्मूलन से मुख्यतः मध्यम कृषक जातियों का एक बड़ा वर्ग प्रभावित हुआ, जिसमें अहीर, कुर्मी, लोधी राजपूत, मौर्य कुशवाहा, सैनी जैसी जातियां शामिल हैं। ये जातियां मनोवैज्ञानिक रूप से अपने पहले के नियन्त्रक जातियों के प्रभाव समाप्त होने से लाभान्वित हुई फिर भी इनका राजनीतिक प्रभाव अभिजात जातियों की अपेक्षा कम रहा। हरित क्रांति से कृषि में उत्पादकता तेजी से बढ़ी इससे मध्यम कृषक जातियों का आर्थिक आधार मजबूत हुआ और ग्रामीण उत्तर प्रदेश में आर्थिक पदानुक्रम में नीचे आने वाले कई जाति समूहों में तेजी से राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। यह ध्रुवीकरण आर्थिक आधार पर छोटी और मध्यम जातियों बनाम बड़ी जातियों के बीच था। उत्तर प्रदेश में मध्यम जातियों के पास बड़ी कृषि जोतें थीं अतः ये कृषक जातियां ग्रामीण उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक ढाँचे को राजनीतिक ध्रुवीकरण के आधार पर प्रभावित करने में सफल रहीं।

कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी ने मुख्यतः धनी किसानों और जमींदारी के हितों का ध्यान रखा स्वतंत्र पार्टी ने 1966 में भूमि सीलिंग को अर्थहीन बताया उसने इसको समाप्त करने, कृषि उत्पादों का ज्यादा मूल्य दिलाने और सिंचाई सुविधाएं बढाने की मांग की। इन पार्टियों के 70% से ज्यादा विधायक धनी किसान थे। पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना के विकास के साथ–साथ नये राजनीतिक दलों का उदय हुआ समाजवादी आन्दोलन के उग्र शाखा के रूप में 1960 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, पार्टी ने मुख्यतः मध्यम किसानों और पिछड़ी जातियों को प्रभावित किया। पार्टी ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने और कृषि के विकास के लिये आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इसका सीधा प्रभाव पिछड़ी जातियों की राजनीतिक चेतना के रूप में सामने आया। कांग्रेस के सामाजिक आधार में तेजी से कमी आयी जैसे ऊपरी दोआब में कांग्रेस को 1952 के चुनाव में 55% मत मिले लेकिन 1969 के चुनाव में पार्टी को केवल 36% मत मिले। 1960 के दशक में पार्टी के सामाजिक आधार में नाटकीय परिवर्तन शुरू हुआ इस काल में ऊपरी दोआब में बाजार उन्मुख और नकदी फसल उत्पादक किसान कांग्रेस की कृषि नीतियों से असन्तुष्ट होने लगा और भारतीय क्रांति दल जैसे राजनीतिक दल पिछड़ी जातियों में तेजी से लोकप्रिय होने लगे 1969 में भारतीय क्रांति दल ने ऊपरी दोआब में 31% मत प्राप्त करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया पार्टी को रूहेलखंड में भी 36% मत प्राप्त हुए।

पिछड़ी जातियों की राजनीतिक एकता का मुख्य आधार हरित क्रांति से पैदा हुई उनकी आर्थिक शक्ति थी। पिछड़ी जातियों ने अपने अखिल भारतीय संगठन बनाने शुरू कर दिये जैसे अखिल भारतीय कुर्मी महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा, अखिल भारतीय मौर्य महासभा। जाति के प्रतीक चिन्हों और नारों का प्रयोग किया गया जिसने पिछड़ी जातियों में राजनीतिक एकता स्थापित कर दी। इसके बाद चौधरीचरण सिंह के रूप में पिछड़ी जातियों को योग्य नेतृत्व प्राप्त हो गया अब मध्यम और छोटे किसान भारतीय क्रांति दल और जनता पार्टी से सम्बद्ध हो गये। पिछड़ी जातियों में राजनीतिक एकता प्राप्त करने के लिए सत्ता अजगर (अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत) की नारा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया। इसका सीधा प्रभाव कांग्रेस के प्रदर्शन पर पड़ा, कांग्रेस के सामाजिक आधार और मतों में निरन्तर गिरावट आने लगी। पार्टी को 1952 में 53% 1957 में 46%] 1962 में 38%] और 1967 में 32% मत मिला। वहीं भारतीय क्रांति दल और लोकदल जैसे दल पिछड़ी कृषक जातियों का नेतृत्व करने लगे। ग्रामीण पिछड़ी जातियों में असन्तोष के दो मुख्य कारण थे –

1. ब्राह्मण और राजपूत जातियों का ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीति में वर्चस्व और नगरों में व्यापार करने वाली जातियों का वर्चस्व।
2. सरकार द्वारा किसानों को कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न दिला पाना।

कांग्रेस का 1967 में विभाजन हो गया और चौधरीचरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल नाम का राजनीतिक दल बनाया, चौधरीचरण सिंह ग्रामीण और कृषक हितों और पिछड़ी जातियों के मुख्य प्रवक्ता के रूप में सामने आये। चौधरीचरण सिंह ने पिछड़ों के नेता के रूप में 1967 के चुनाव लड़ा और 1971 के संसदीय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया। 1969 के बाद राजनीति में मध्यम पिछड़ी जातियों का वर्चस्व साफ नजर आने लगा कांग्रेस भी पिछड़ी जातियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई यादव जाति के नेताओं को आगे ले आई। 1969 से 1977 के बीच पिछड़ी जातियों में राजनीति चेतना तेजी से विकसित हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी आन्दोलन कमजोर हो गया और संयुक्त समाजवादी पार्टी का भारतीय क्रांति दल में विलय, इससे भारतीय क्रांति दल को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने समर्थन में सन्तुलन प्राप्त हो गया अब भारतीय क्रांति दल का नया नाम भारतीय लोकदल हो गया और पार्टी का मध्यम पिछड़ी जातियों में प्रभाव और व्यापक हो गया। अब पार्टी को जाट, यादव, कुर्मी, लोधी राजपूत और मौर्य कुशवाहा जैसी पिछड़ी जातियों का समर्थन प्राप्त हो गया। वहीं कांग्रेस अब मुख्यतः ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों के समर्थन पर आधारित हो गयी। पिछड़ी जातियों के राजनीतिक एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव 1977 के चुनाव में दिखा जनता पार्टी को जाटों, यादवों सहित अन्य पिछड़ी जातियों का पूरा समर्थन मिला। जनता पार्टी को 1977 के चुनाव में सफलता मुख्यतः तीन सामाजिक शक्तियों के गठजोड़ का परिणाम थी। मुख्यतः मध्यम और पिछड़ी जातियों का समर्थन, मुसलमानों और अनुसूचित जातियों का समर्थन, जो आपातकाल के कारण कांग्रेस से असंतुष्ट थीं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1967–1977 के बीच पिछड़ी जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका उभरकर सामने आयी। हरित क्रांति ने पिछड़ी जातियों में राजनीतिक असंतोष को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ी जातियां केन्द्रीय भूमिका में आ गई। आजादी के बाद से कांग्रेस की रणनीति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशाली जातियों का समर्थन प्राप्त करना था। मुस्लिमों को भी कांग्रेस में समर्थन मिला जबकि अनुसूचित जातियों को वोट बैंक के रूप में कांग्रेस ने प्रयोग किया। कांग्रेस कभी भी पिछड़ी जातियों में मजबूत जनाधार नहीं बना पायी। 1967 में चरण सिंह के पार्टी छोड़ने से पार्टी का जनाधार और भी कम हो गया। 1969 में कांग्रेस के देश व्यापी विभाजन के बाद कांग्रेस कमजोर हो गई जिससे पिछड़ी जातियों को उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करने का अवसर मिल गया। अब पिछड़ी जातियां मुख्यतः चरण सिंह के नेतृत्व के रूप में राजनीतिक रूप से लामबन्द हो गयीं परिणामतः कांग्रेस का आधार तेजी से कमजोर हुआ। कांग्रेस का मुख्य आधार बड़े कृषक, पूर्व जमींदार, ब्राह्मण और राजपूत थे लेकिन संख्या के आधार पर यह गठबंधन कमजोर था, अतः कांग्रेस को मुसलमानों और दलितों के समर्थन की आवश्यकता थी। पिछड़ी जातियों ने इसे एक चुनौती और अवसर के रूप में देखा और चुनावों में कांग्रेस को तगड़ी चुनौती दी। पिछड़ी जातियों की शक्ति कई कारणों से बढ़ गयी, जमींदारी उन्मूलन से प्राप्त लाभ, पंचायतों का गठन, सहकारी संस्थाओं का गठन, भूमि की चकबंदी, हरित क्रांति और ग्रामीण स्तर की विकास योजनाओं से पिछड़ी जातियां राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हो गयीं। भूमि पर नियन्त्रण ने पिछड़ी जातियों को स्थानीय प्रभुत्व प्रदान किया पिछड़ी जातियां संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में काफी

ज्यादा थीं, लेकिन मध्यम कृषक जातियां संख्या में अधिक होने के बाद भी आंतरिक विभाजन और संघर्ष के कारण संगठित नहीं हो पायीं। हरित क्रांति के कारण कृषकों के हितों के कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आये इन मुद्दों से कृषक पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ और पिछड़ी कृषक जातियां अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक सौदेबाजी की शक्ति विकसित करने में सफल रहीं अब उत्तर प्रदेश में कृषक हित शहरी पूँजीपति लोगों के हितों से महत्वपूर्ण बन गये क्योंकि पिछड़ी कृषक जातियों ने सामूहिक रूप से राजनीतिक सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त कर लिया चौधरीचरण सिंह का कांग्रेस छोड़ना, समाजवादी आन्दोलन का बिखराव और इसका भारतीय क्रांति दल से जुड़ना, 1974 में लोकदल और दलित मजदूर दल किसान पार्टी का जनता गठबंधन से जुड़ना यह सभी तथ्य प्रदेश में पिछड़ी जातियों के असंतोष और महत्व को अभिव्यक्त कर रहे थे पिछड़ी जातियों ने कांग्रेस के विरोध को मुख्य आधार बनाया चौधरीचरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल बनाकर पिछड़ों के राजनीतिक असंतोष को राजनीतिक मंच प्रदान किया। 1977 के चुनाव में गैर कांग्रेसी पार्टियों की एकजुटता के कारण भी पिछड़ों की राजनीतिक शक्ति स्पष्ट हुई और जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया।

हरित क्रांति से प्राप्त आर्थिक लाभों ने पिछड़ी जातियों को अपनी शक्ति पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यद्यपि पिछड़ी जातियों में राजनीतिक असंतोष पहले ही प्रारम्भ हो चुका था, कानपुर के स्वामी अच्चिदानन्द, कानपुर के स्वामी मल्लाद, एस. डी. चौरसिया जैसे नेताओं ने पिछड़ी जातियों को राजनीतिक रूप से संगठित किया स्वामी बोधानन्द महास्थविर ने पिछड़े हिन्दुओं को राजनीतिक रूप से संगठित किया। अखिल भारतीय यादव महासभा ने अपने समुदाय के लोगों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यादवों की खेतिहर जातियों से आपसी भाईचारे की भावना का विकास हुआ जिससे अजगर जैसे आन्दोलन का जन्म हुआ। पिछड़ी जातियों के सम्मेलनों में ऊँची जातियों के विरोध को उत्तेजना दी जाती थी और उन्हें शोषक और प्रगति में बाधक माना जाता था। हरित क्रांति से प्राप्त आर्थिक स्थिति और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाने के कारण जाट, यादव और कुर्मी जातियां सवर्णों के साथ बराबरी का दावा करने लगे अब यादव, कुर्मी और जाट जैसी जातियों ने अन्य कमजोर पिछड़ी जातियों का नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त कर लिया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा के. एल. – भारतीय समाज
2. काका कालेलकर रिपोर्ट 1955
3. सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट (छेदीलाल साथी आयोग) 1975
4. सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट – 2001 उत्तर प्रदेश सरकार
5. ब्रास पाल – कास्ट इन उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स
6. उत्तर प्रदेश में कृषि गणना – राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश 1970–1971
7. अहमद जेड. ए –. सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल लैण्ड
8. सिंह बलजीत और मिश्रा श्रीधर ए स्टोरी ऑफ लैण्ड रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश
9. जानसन माइकल – रिलेशन बिटबिन लैण्ड सेटलमेन्ट एण्ड पार्टी पालिटिक्स इन उत्तर प्रदेश
10. मार्कस फ्रान्टा – पालिसी रेसपान्सेड टू इन्डियाज ग्रीन रेवुलेशन

Copyright © 2016 *Dr Sushil Pandey*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.